



CY

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

श्रीभक्तार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ल. 76)

वर्ष विल्सो, मुद्रिकार, अनवरी 29, 1992/माघ 9, 1913

No. 76) NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 1992/MAGHA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी आसी है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

परिचय और बन संकालन

अधिसूचना

नई विल्सो, 29 जनवरी, 1992

पर्यावरण अनापनि वर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की
धारा 3(1) और धारा 3(2)(v) तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम,
1986 के नियम 5(3)(क) के अधीन

का, द्वा. 83(अ).—प्रत्यक्षिक मूदा कटाय और कठिनय विकासात्मक
क्रियाकलापों के कारण जल और धारा प्रदूषण से पर्यावरण की पर्यावरण
के कारण प्रत्यक्षिक प्रतिकूल पर्यावरणाय प्रभाव पानि हुआ है, जिससे “
केवल प्राकृतिक स्रोतों जैसे जगल, कबूल जनसंपत्ति, प्राकृति भूमि, मरियों,
ज़ीरों, जैनी पूल प्रारक्षितियां और बनस्पति सुरक्षा के विनाश को संकट
पैदा हुआ है, जो देश के यहे भागों में तेजा से महत्व ले रहे हैं, जिन्हें
उससे जीव माल पशु और मानव दोनों के स्वास्थ्य भार उत्तरजाविता
पर भी प्रभाव पहुंचता है,

और यह आवश्यक है कि प्राकृतिक स्रोतों पर जीव सम्पाद्य के
दबाव के साथ ही वायु, जल और भूमि के प्रदूषण पर जो इन्हा गहरा
है कि हमारे प्राकृतिक, जैविक और आनुवंशिक सम्पन्नि को गम्भीर खतरा

हो गया है, नियंत्रण करके पर्यावरण का संरक्षण किया जाए और उसकी
नवालिटी को संशारा जाए;

और कठिनय विकास परियोजनाएं प्रतिष्ठिति पद्धति से परिवर्तित
इरियों से परे स्थायमंगत अवस्थिति में प्रतिष्ठिति की बहुत कमता
के भीतर बहुत जानी चाहिए, जो अस्थिया प्रतिकूल के अवैतन जाएंगी,
जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकासात्मक कार्यकलाप
पर्यावरण और उसके विकास के माथ तापमेल रखते हुए किए जाते हैं;

और पूर्वोक्त उद्देश्य प्रत्येक परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव निवारण
और परियोजना के प्रारम्भ से ही प्रतिकूल प्रभाव के निवारण, विलोपन
या न्यूनीकरण के लिए प्रारक्षित पर्यावरण प्रबन्ध योजना के प्रावाह पर
किसी क्षेत्र में भ्रष्टस्थित किए जाने के लिए प्रस्थापित कियों परियोजना
के माध्यमानीपूर्वक निवारण हारा प्राप्त किए जा सकते हैं;

यह, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(1986 का 29) का धारा 1 का उपधारा (1) और उपधारा (2) के
खण्ड (5) हारा प्रवल शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशित करनी है
कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उत्तरियम (3)
के खण्ड (अ) के अधीन इस अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन का तारीख

से ही भनुसूची 1 या भनुसूची 2 में सूचीबद्ध किसी नई परियोजना, विद्यमान उद्योग या परियोजना का विस्तारण या आधुनिकीकरण भारत के किसी भी भाग में हाथ में नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसे इस प्रधिसूचना में इसके पश्चात विनियिट प्रक्रिया के भनुसार, यथाविधि, केन्द्रीय सरकार या संघविधि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापति न घनुपति कर दी गई हो।

2. भनुसूची 2 से प्रत्यक्षिण किसी भात के होते हुए भी भारतीय लैंगिकों या अभिहित परिवारिक रूप से सुग्राही लौल की सीमा के दस किलोमीटर के भीतर अध्यया राष्ट्रीय उद्यान या शरण स्थान की सीमा के 25 किलोमीटर के भीतर अवशिष्ट किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी परियोजना को केन्द्रीय सरकार से पर्यावरण संबंधी अनापति की आवश्यकता होगी।

3. भनुसूची 1 और भनुसूची 2 में प्रत्यक्षिण किसी भात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और बन मंत्रालय किसी राज्य सरकार द्वारा किसी परियोजना को दो गई पर्यावरण संबंधी अनापति का उन्नीश्विकान कर सकेगा यदि—

(क) उस मंत्रालय को प्रभावित पक्षकारों से ऐसी अनापति के विषय कोई लिखित अस्थावेदन प्राप्त होता है, या

(ख) यह प्रथम युद्धया स्टॉट है कि उस मंत्रालय द्वारा विनियिट पर्यावरणीय संबंधी प्राकारणों और समिक्षणों की संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसी अनापति देते समय अवहेलना की गई है।

4. परियोजना की पर्यावरण संबंधी अनापति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया :— (1) कोई व्यक्ति जो भारत के किसी भाग में किसी परियोजना की अध्यया भनुसूची 1 और भनुसूची 2 में सूचीबद्ध किसी विद्यमान उद्योग या परियोजना के विस्तारण या आधुनिकीकरण को हाथ में लेना चाहता है, सर्विद, पर्यावरण और बन मंत्रालय नई दिल्ली, को जहाँ पर्यावरण संबंधी अनापति केन्द्रीय सरकार से अपेक्षित है, या संबंधित राज्य सरकार के पर्यावरण संबिल को, अर्हा राज्य सरकार से पर्यावरण संबंधी अनापति अपेक्षित है, एक आवेदन देजेगा। यह आवेदन इस अधिसूचना से संलग्न प्रोकार्मी (उपायकारी) में किया जाएगा और उसके साथ परियोजना की अविरोध रिपोर्ट होगी जिसमें अस्थ बातों के साथ-साथ पर्यावरण संबंधी प्रभाव निवारण रिपोर्ट और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और बन मंत्रालय द्वारा आरो किए गए मार्गदर्शक सिफारिशों के भनुसार तैयार की गई पर्यावरण प्रबन्ध योजना होगी।

(2) निम्नलिखित स्थल विनियिट परियोजनाओं की बाबा मे—

(क) बनन;

(ख) निट हैड़ उष्मीय शक्ति केन्द्र;

(ग) हाइड्रो जल विधुत शक्ति परियोजना; और

(ज) बहु उष्मीय नदी घाटी परियोजना,

केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और बन मंत्रालय से ऐसों का काटना, किसी भी प्रकार का अस्थायी या स्थायी बेधन, बोदना या संश्योग अन्तर्भूति करने वाला कोई अन्वेषण प्रारम्भ करने से पूर्व प्रारम्भिक स्थल संबंधी अनापति अपेक्षित होगी।

उक्त स्थल संबंधी अनापति बंजार की गई अनुसार के लिए भनुसूचना की आएती और समिक्षण प्रारम्भ करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमाला होगी।

(III) (क) आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई अविरोध परियोजना रिपोर्ट का, यथाविधि, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रधान विवरण अधिकरण द्वारा, इस अधिसूचना की भनुसूची 3 में विनियिट संरक्षण वाली विशेषज्ञ समिति के परामर्श से मूल्यांकन और निवारण किया जाएगा।

(ख) उक्त विशेषज्ञ समिति को परियोजना से संबंधित संकियाओं के प्रारम्भ से पूर्व, उनके दौरान या उनके पश्चात् किसी समय, यथाविधि, स्थल या कारबाना परिसरों में प्रवेश करने और उनका विरोध करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(ग) प्रभाव निवारण अधिकरण दस्तावेजों के तकनीकी निवारण और परियोजना प्रविकारियों द्वारा किए गए आकड़ों, जो स्थल अध्यया कारबाने में की गई यात्राओं के दौरान संग्रहीत आकड़ों द्वारा अनुपूरित होंगे। प्रभावित जनसंख्या और पर्यावरण संबंधी समूहों की अस्थ: किया पर अधारित रिपोर्टिंग दैधार करेगा। वे सिफारियों और जारी जिनके अधीन रहते हुए पर्यावरण संबंधी अनापति वीं गई है, संबंधित पक्षकारी को उपलब्ध कराई जा सकती है। निवारण अपेक्षित दस्तावेजों की और परियोजना प्राविकारियों से आकड़ों की प्राप्ति पर तीन भास की कालावधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(IV) संबंधित प्रभाव निवारण अधिकरण दो मिफारियों के प्रभावी कार्यालय और उन शर्तों को, जिनके अवैध पर्यावरण संबंधी अनापति वीं गई है, मानिटर करने के लिए संबंधित परियोजना प्राविकारियों संबंधित अधिकरण को उमा ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

5. हम अधिसूचना से प्रत्यक्षिण प्रस्तावित निवेशों के विलम्ब कोई अपति फाइल करने में हितबद्ध कोई व्यक्ति सिखित रूप में सचिव पर्यावरण और बन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स, औरी रोड, नई विली के पास राजपथ में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छाड़ दिन के भीतर फाइल कर सकेगा।

[सं. जे-12013/4/89-पार्ट ए-1]
प्राप्त. राजेश्वरी, सचिव (ई और एफ)

भनुसूची 1

केन्द्रीय सरकार से पर्यावरणीय निवारण की अपेक्षा रखने वाली परियोजनाओं की सूची

1. परमाणु शक्ति
2. तापीय शक्ति
3. बहु उष्मीय नदी घाटी परियोजनाएं
4. पर्यावरण, बंवरगाह और विमानपत्तन
5. रेल पथ (जिसमें गैर रेल पथ भूमि का घर्जन भी सम्मिलित है)
6. परिष्करण
7. उर्वरक
8. नाशक जीवमार और फौटोनाशी
9. पेट्रोलियम

10. विस्फोटक और उपसाधन
11. औषधि और औषधि निर्माण (विनिर्मिति के सिद्धांत)
12. प्लास्टिक उत्पादन
13. रबड़ संशिलष्ट
14. एस्बेस्टास और एस्बेस्टास उत्पाद
15. सोडियम और पोटाशियम साइलाइड
16. प्राथमिक धातुकर्मीय उद्योग (जस्ता, सीसा, तांबा, एस्युरिनियम और इस्पात)
17. एफीएन इस्पात संयंत्र
18. ट्रक, जीप, वार और ग्रन्य भारी यानों के टायर/ट्रूब
19. क्षार (एस ए ओ एच)
20. एकीकृत पेंट कार्मिलेम्स
21. मानव निर्मित फाइबर (संशिलष्ट और अर्द्ध संशिलष्ट, रेपान, नायलोन और पालिएस्टर)
22. भीसा प्रक्रमण सहित भंडारण बैट्री।
23. परिमेट्रियल अपशिष्ट और यलोरीनित हाहड़ोकार्बन के लिए भर्त्यीकरण संयंत्र
24. अनुसूची 2 में लिनिदिट से ऊपर ऐसी सभी परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक मालदंड।

अनुसूची 2

राज्य सरकार ने पर्यावरणीय निर्धारित की अपेक्षा रखने वाली परियोजनाओं की शूष्ठी

(यांच्चूनमानो के दैरा 2 के उपर्योग के मध्यमें रहते हुए)

परियोजना की प्रकृति

प्रारंभिक मालदंड (यदि कोई हैं)

1. मूसिका शिल्प
2. घोयला प्रकाशक
3. दुष्टिकारण
4. कार्बनिकरण संयंत्र
5. इंजीनियरी (नलिका, संचक, रोलिंग मिल)
6. उच्चताप मह
7. पाइप पथ (मार सी सो, इसाम, सीबनहीन)
8. ऐल्यूमियम कार्बाइड
9. कार्बन ब्लैक
10. स्नेहक सेस
11. कांच
12. औषधि और औषधि निर्माण (विनिर्मिति)
13. विद्युत लेपन
14. भंडारण बैट्री (ऐर सीसा प्रक्रमण)
15. क्षार (एस ए 2, सी ओ 3 और सी ए सी ओ 3)
16. प्लास्टिक प्रक्रमण (एस डी पी ही, एस एस डी पी ही ही, पी डी सी, पी पी आदि)
17. दोपहिया और साइकिल रिक्षा का टायर/ट्रूब।
18. सभी प्रकार के टायरों का निर्बन्धन।
19. पेंट (बांसी, आरकोल रसायन, वर्णक)
20. रेजक इकाई उद्योग
21. नायन और अपमार्जक
22. खाद्य प्रसंस्करण (मास, मछली, प्राणिजन्य उत्पाद)
23. दुध प्रसंस्करण
24. कामज उत्पाद
25. गैर परिमेट्रियल अपशिष्टों के लिए भर्त्यीकरण संयंत्र।

क्रमांक	विवरण	जटिलता अनुमान
26.	जल विद्युत उपकरण	उत्पादन क्षमता
(क)	नई परियोजनाएँ	10 मेगावाट तक
(ब)	चिन्हामान नहर या चिन्हामान धारा पर पहले से ही अमूल्यापन पेनस्टान महिल मध्ये विद्युत गुहों का पता लगाना।	10 मेगावाट तक
27.	सीमेट	200 टन प्रतिविवर तक
28.	इस्पात संयंक	50,000 डी.पी.ए. तक
29.	धमड़ा जर्मशोधन	5,000 खाल प्रतिविवर तक
30.	आसवन	150 किलोमीटर प्रतिविवर तक
31.	चीनी	1000 टन प्रतिदिन गमन तक
32.	टेक्सटाइल	500 मीटर प्रतिदिन तक
33.	लुगरी, कागज और अखबारी कागज	33,000 टन प्रतिदिन तक
34.	रेजक माहद्यम	5 टन प्रतिविवर तक
35.	नाप दृढ़, फीनोल और यूरिया फार्मल्डेहाइड	5000 टन प्रतिदिन तक
36.	प्रायग	500 टन प्रतिविवर तक
37.	यन्त्रायांत्रिक प्रसंस्करण	500 टन प्रतिविवर तक
38.	दसाई	एकलागत 20 करोड़ तक
39.	संचार	एकलागत 20 करोड़ तक
40.	समुद्र से एक किलोमीटर की ऊँचाई की सतह या 10000 सॉटर की 3.जाई के भोतर प्रैंटर और अन्य परियोजनाएँ।	6000 लक्ष तक
41.	गिराई	प्रैंटर
42.	खनन	2000 लक्षटर कमाह क्षेत्र तक
43.	सूरक्षा (हिमालय और उसकी वन धूमि में)	5 हेक्टर पट्टा तक
44.	औद्योगिक सम्पदा	5 किलोमीटर लंबाई तक
45.	औद्योगिक शहरी क्षेत्र नया और विस्तारित।	100 घूमिट
		5000 आवासीय घूमिट

मनसार्थी- 3

पर्यावरणीय प्रभाव निधरिण के लिए बिधेयक, समितियों की सरजना

विनालिकात से भिन्नकर बने प्रस्त्रेक विकास थोक में सकारीकी विशेषज्ञों से गठित विशेषज्ञ समितियाँ, केन्द्रीय या राज्य स्तर पर विकास सेक्टरों का व्यवहार और विप्रार्थ करेंगी।

१. सुशेषत खिकास सेटटर मे ऐसा प्रविशालाली और अनुभव पर्याप्तिकी विज्ञानी या पर्यावरणीय विज्ञानी या तकनीकी वृत्तिक जिम्मेदारी; रशीक संरक्षण और किए जाने योग्य खिकास मे अधिकारि प्रबोधित की हो—अधिकारी।

विष्णुप्रसाद सरस्वती

ऐसे सवाल जो सुरंगत क्षेत्र में एस, टैक/पी.एस, डी. हैं और जिनके द्वारा सुरंगत विकास सेक्टर में पर्यावरणीय प्रदर्शन में कम तो कम ५ बर्बे के अनुभव के साथ दीर्घकालीन अन्वयन है;

- परिस्थितिको संबंध प्रवृत्ति का मायह ही संबंध प्रवृत्ति और प्रतिक्रियण घनभूमि
- मायु प्रवृत्ति नियंत्रण
- जल प्रवृत्ति नियंत्रण
- घनस्पति/प्राणी संवर्धन और प्रवृत्ति
- जल संमाधन प्रवृत्ति
- भूमि उपयोग योगना/नियमीकृत भूमि का जैव उद्योग
- जलीय जीवनका संवर्धन और संरक्षण

9-10 परिस्थितिकी योजना (2)

11 निर्वाचित परियोजना के पुनर्वास के अनुभव के साथ मामाजिक वैज्ञानिक

12 अध्यात्म और पर्यावरण आंदोलन वी एड भूमि का विशेषज्ञ

13-14. नुसगन त्रिकास सेप्टरमें विधय क्लेश विशेषज्ञ (2)

15 और भरकारी गास्थान पर्यावरणीय आनंदांग समूह का प्रतिनिधि

16 केंद्र/राज्य में प्रभाव नियंत्रण अधिकारण का प्रतिनिधि।

मरम्म-मचिव

टिप्पणी - विशेषज्ञ, अपनी व्यष्टिक अमना के अनुसार काय करेंगे मिथाएं उनके जिन्हें विधिवाल्प से प्रतिनिधि नामितिष्ठ किया गया है।

उपाख्य

प्रावधन प्रणव

1. (क) इत्याक्षित पार्योजना का नाम और प्रकार

(ख) परियोजना की अवस्थिति

(ग) आनंद का नाम

(ज) जन्मा, तद्देश्य

(अ) अध्याय/विषय

(म) समीक्षक विमान वनन/रक्षक व्येषण

(ग) परिवित युक्तिक स्थल और परिवित स्थल के लिए कारण

2. परियोजना के उद्देश्य

(क) भूमि अपक्षा

(ख) भूमि

(ग) वन भूमि और वनस्पति का विवर

(ग) अध्ययन (विनायिष्ट करें)

(ख) (1) आवाह में भूमि उपयोग/प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी., जो परिवित हो भीतर

(2) भविष्यत, अभियुक्ता और रहने वाला को दायरे हुए क्षेत्र की स्थितावृत्ति

(3) धारण की सुधारेता

(ग) 10 कि.मी., की परियोजना में विविध वनस्पति स्त्रोत और उनका वायु, जल तथा भूमि की गुणवत्ता पर प्रभाव।

(ख) समीक्षक राष्ट्रीय उद्घान/प्रभयारण्य/आरक्षित/जीष्मंडल/संस्मारक/पर्यावरण/आरक्षित वन की दृष्टि।

(ग) अवानों/उद्घार कोनों के लिए पुनर्वास योजना

(ग) हरित पट्टा योजना

(ग) प्रतिकरात्मक वनरोपण योजना

4. जलवायु और थायु की गुणवत्ता

(क) ग्लोबल पर वर्नोरण

(ख) वार्षिक अधिकतम/न्यूनतम/माध्यमिक तापमान

(ग) प्रतिवार्षिक वायु विवरण

(ग) यज्ञवान/द्वौरमें रो/बृहिष्टि प्रस्फोट की वार्ता

(क) परिवेश धार्या गुणवत्ता भांकड़ा
 (ख) परियोजना से उत्सजित एवं नी एम रेसों
 (सी और, यो २, एस और २, एल और २, सी एच एल
 आदि) की प्रकृति प्रौद्योगिकता

5. (क) जल-संग्रहन स्थल
 (ख) गुणकीय मौजूदा जल उपलब्धता, जल अपेक्षा
 (ग) प्रतियोगी उपयोगिताओं (नर्दी, हील, भूमि और प्रदाय) से टेप किया जाने वाला स्थोल
 (घ) जल गुणवत्ता
 (ङ) गत 15 वर्षों से भूमिगत-जल में मंत्रेशिस परिवर्तन और बदलाव परिवर्तन उपरा निवारण इन्हीं
 (ज) (1) उपचार र्मांशों के साथ छांडे जाने वाले अपरिषट् जल की प्रमाणा
 (2) अपरिषट् जल के व्यवन के पहले और बाद में ग्राही स्थान पर जल की गुणवत्ता की प्रमाणा
 (छ) (1) आवश्यक आवाहन उपचार योजना के साथ कूंड जल की गुणवत्ता के घोरे
 (2) प्रभाव ग्रेड चिकित्सा योजना

6. डोस अधिग्रहण
 (क) निरसन व्यवन के लिए जनित ठांब अपग्रेडों की प्रकृति और मात्रा
 (ख) धार्या जल और भूमि के आग होने वाले प्रदूषण के निकारण के लिए टास अपरिषट् अपने रीति

7. शोर और कम्पन
 (क) शोर और कम्पन के स्रोत
 (ख) परिवेश शोर इंटर
 (ग) प्रमाणित शोर और कम्पन नियवण उपाय
 (घ) नियवण उपाय में अवलम्बन समस्या, यदि कोई हो

8. प्रदाय के स्रोतों में धरणों की गांधीजी की प्रवेश्या; यदि स्वैतिक शार्कित एवं का प्रहनाल हो, तो पूर्ण पर्यावरणीय व्यावेरण से दे

9. झीरों के साथ अधिनियोजित किया जाने वाला आवधकतम श्रम इल
 आयंडल की आरम्भिक छातीयों के माध्यम से स्वास्थ्य प्राप्तिति- श्रमिकों और कर्मचारिजून, जोनों की ओत में अपरिषट्/भूमि से उत्पन्न रीतों के कारण स्थानिक स्वास्थ्य समस्याएं
 प्रस्तावित स्वास्थ्य पठति

10. (क) शामों की संक्षया और अन्तर्भुक्त उपचारित की जाए
 (ख) पुनर्वासन मास्टर लाइ

11. मकट प्रबंध योजना के साथ जीवित निवारण रिपोर्ट
 12. (क) परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट
 (ख) पर्यावरणीय प्रभाव निवारण रिपोर्ट
 (ग) पर्यावरणीय प्रबंध योजना

13. पर्यावरणीय प्रबंध कथा का विस्तृत व्यौरा

14. धार्या और जल की गुणवत्ता निगरानी केरों का आपात किया जाना

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
FORESTS
NOTIFICATION**

New Delhi, 29th January, 1991

[Under Section 3(1) and Section 3(2) (v) of Environment (Protection) Act, 1986 and Rule 5(3)(a) of Environment (Protection) Rules, 1986 on Environment Clearance].

Whereas considerable adverse environment impact has been caused due to degradation of the environment with excessive soil erosion and water and air pollution on account of certain development activities, thereby engendering not only the destruction of natural resources like forests, mangroves, wetlands, rivers, lakes, genepool reserves and vegetation cover which is fast dwindling in large parts of the country, but also affecting the health and very survival of living beings both animal and human;

And whereas it is necessary to protect and improve the quality of environment by controlling pollution of air, water and soil along with biotic pressure on natural resources, which is so intense that our natural biological and genetic wealth is threatened with severe damage;

And whereas certain development projects should be carried on within the carrying capacity of the ecosystem through judicious location beyond defined distances from eco-systems which will otherwise come under stress, so as to ensure that developmental activity takes place in harmony with the environment and improvement thereof;

And whereas the aforesaid goals can be achieved only by careful assessment of a project proposed to be located in any area, on the basis of an environmental Impact Assessment of each project and the necessary Environment Management Plan for the prevention, elimination or mitigation of the adverse impacts, right from the inception stage of the project;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby directs that on and from the date of the final publication of this notification under clause (d) of Sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the expansion or modernisation of any existing industry or new projects listed in Schedule I or Schedule II shall not be undertaken in any part of India, unless it has been accorded environmental clearance by the Central Government or, as the case may be, the State Government concerned in accordance with the procedure hereinafter specified in this notification.

2. Notwithstanding anything contained in Schedule-II, any project proposed to be located within 10 kilometers of the boundary of reserved forests, or a designated ecologically sensitive area, or within 25 kilometers of the boundary of national park or sanctuary, will require environmental clearance from the Central Government.

3. Notwithstanding anything contained in Schedules I and II, the Central Government in the Ministry of Environment and Forests may review the environmental clearance given to any project by any State Government if :

- (a) written representation is received by that Ministry against such clearance from the affected parties or
- (b) it is prima facie evident that environmental imperatives and norms specified by that Ministry have been ignored by the State Government concerned while giving such clearance.

4. Procedure for seeking environment clearance of projects.—(I) Any person who desires to undertake any project in any part of India or the expansion or modernisation of any existing industry or project listed in Schedules I and II shall submit an application to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, New Delhi, where environmental clearance is required from the Central Government, or to Environment Secretary of the State Government concerned, where the environmental clearance is required from the State Government. The application shall be made in the proforma appended to this notification and shall be accompanied by a detailed project report which shall, inter alia, include an Environmental Impact Assessment Report and an Environment Management Plan prepared in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(II) In case of the following site-specified projects :

- (a) mining;
- (b) pit-head thermal power stations;
- (c) hydro-electric power projects; and
- (d) Multi-purpose river valley projects.

a preliminary site clearance will be required from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests before initiating any investigations involving cutting of trees, drilling, digging or construction of any sort temporary or permanent.

The said site clearance will be granted for the sanctioned capacity and will be valid for a period of 5 years for commencing the construction.

(III) (a) The detailed project report submitted with the application shall be evaluated and assessed by the Impact Assessment Agency of the Central Government or, as the case may be, of the State Government in consultation with a committee of Experts, having a composition as specified in Schedule III to this notification.

The said Committee of Experts will have full right of entry and inspection of the site or, as the case may be, factory premises at any time prior to, during, or after the commencement of the operations relating to the project.

(c) The Impact Assessment Agency will prepare a set of recommendations based on technical assessment of documents and data furnished by the project authorities, supplemented by data collected during visits to the site or factory, interaction with affected population and environmental groups. The recommendations and the conditions subject to which environmental clearance is given may be made available to concerned parties. The assessment shall be completed within a period of 3 months on receipt of the requisite documents and data from the project authorities.

(IV) In order to enable the Impact Assessment Agency concerned to monitor the effective implementation of the recommendations and conditions subject to which the environmental clearance has been given, the project authorities concerned shall submit a half-yearly report to the concerned agency.

5. Any person interested in filing any objection against the proposed directions contained in this notification, may do so in writing to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Parivar Bhavan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi within 60 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. Z-12013/4/89-IA-I]

R. RAJAMANI, Secy. (EKF)

SCHEDULE-I

LIST OF PROJECTS REQUIRING ENVIRONMENTAL CLEARANCE FROM THE CENTRAL GOVERNMENT

1. Atomic Power
2. Thermal Power

3. Multi-purpose River Valley Projects
4. Ports, Harbours and Airport
5. Railway lines (involving acquisition of non-railway land)
6. Refineries
7. Fertilizers
8. Pesticides and Insecticides
9. Petrochemicals
10. Explosives and Accessories
11. Drugs and Pharmaceuticals (except formulations)
12. Production of Plastics
13. Rubber-Synthetic
14. Asbestos and asbestos products
15. Sodium or Potassium Cyanide
16. Primary metallurgical industries (Zinc, Lead, Copper Aluminium and Steel)
17. Integrated Steel Plants
18. Tyres/tubes of trucks, jeeps, cars and other heavy vehicles.
19. Alkalies (Na OH)
20. Integrated Paint Complex.
21. Man-made fibres (Synthetics & semi-Synthetics, Rayon, Nylon and Polyester)
22. Storage batteries with lead processing
23. Incineration plants for hazardous waste and chlorinated hydrocarbons.
24. All projects with threshold criteria above those specified in Schedule-II

SCHEDULE-JI

LIST OF PROJECTS REQUIRING ENVIRONMENTAL CLEARANCE FROM THE STATE GOVERNMENT

(Subject to the provisions of para 2 of the notification)

Nature of Projects	Threshold Criteria (if any)
1. Ceramics	
2. CoalWashery	
3. Briquetting	
4. Carbonising Plant	
5. Engineering (Tubings, Castings, Rolling Mills)	
6. Refractories	
7. Pipelines (RCC, Steel, Seamless)	
8. Calcium Carbide	
9. Carbon Black	
10. Reprocessing Lubricating Oil	
11. Glass	
12. Drugs and Pharmaceuticals (Formulations)	

13. Electroplating	
14. Storage Batteries (non-lead processing)	
15. Alkalies (Na_2CO_3 and CaCO_3)	
16. Plastics Processing (HDPE, LLDPE, LDPE, PVC, PP, etc.)	
17. Tyres/Tubs of two-wheelers and cycle rickshaws	
18. Retreading of all types of tyres	
19. Paints (Varnish, Coal Tar Chemicals, Pigments)	
20. Dye Single Industry	
21. Soaps and detergents	
22. Food Processing (Meat, Fish, Animal Products)	
23. Milk Processing	
24. Paper Products	
25. Incineration Plants for non-hazardous waste	
PRODUCTION CAPACITY	
26. Hydro-electric power	
(a) New projects	Upto 10 MW
(b) All power houses to be located on existing canal falls or existing dams with already embedded penstocks.	Upto 10 MW
27. Cement	Upto 200 TPD
28. Steel Plants	Upto 50,000 TPA
29. Leather Tannery	Upto 5,000 Skins PD
30. Distilleries	Upto 150 KLD
31. Sugar	Upto 4,000 TPD cane
32. Textile	Upto 500 Mts/d
33. Pulp, Paper & Newsprint	Upto 33,000 TPA
34. Dye Intermediates	Upto 5 TPD
35. Thermosets Phenol and Urea formaldehyde	Upto 5,000 TPD
36. Acids	Upto 500 TPD
37. Vegetable Oil Processing	Upto 500 TPD
CAPITAL COST	
38. Foundries	Upto Rs. 20 crores
39. Communications	Upto Rs. 20 crores
40. Tourism and other projects written 1 Km. of HTL of sea, or at locations with an elevation of more than 1000 mts.	Upto Rs. 5 crores
AREA	
41. Irrigation	Upto 2000 Hectare command
42. Mining	Upto 5 hectare release
43. Roads (in Himalayas or involving forest land)	Upto 5 kms. length
44. Industrial Estates	Upto 100 units
45. Industrial Township (New & Expansion)	Upto 5000 dwelling units

SCHEDULE III

COMPOSITION OF THE EXPERT COMMITTEES FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT.

The evaluation and assessment of development projects at the Central or State level will be undertaken by Expert Committees consisting of technical experts in each development section constituted as under :

1. An outstanding and experienced ecologist or environmentalist or technical professional in the relevant development sector having demonstrated interest in Environment Conservation and sustainable development.

EXPERT MEMBERS

Members with M. Tech.|Ph. D. in the relevant field and long experience including at least 8 years experience in environmental management in relevant sectors :

2. Eco-system Manager with Systems Management & Modelling Experience.
3. Air Pollution Control.
4. Water Pollution Control.
5. Flora|Fauna Survey & Management
6. Water Resources Management
7. Land Use Planning|Biological reclamation of degraded lands.
8. Conservation & Protection of Aquatic Life.
- 9.10. Ecologists (2)
11. Social Scientist with experience of rehabilitation of project oustees
12. Specialist with background of economics and project appraisal.
- 13-14. Subject area Specialist in relevant development sector (2).
15. Representative of NGO|Environmental Action Groups.
16. Representative of Impact Assessment agency at Centre|State. . . Member Secretary.

Note : Experts inducted will serve in their individual capacities except those specifically nominated as representatives.

ANNEXURE

APPLICATION FORM

- (1. (a) Name & Address of the project proposed :
- (b) Location of the projects :

Name of the place :

District, Tehsil :

Latitude'Longitude .

Nearest Airport|Railway Stn.:

- (c) Alternate sites examined and the reasons for the site proposed :

2. Objectives of the project :

3. (a) Land Requirement :

Agriculture land :

Forest land and Density of vegetation.

Other (specify) :

- (b) (i) Landuse in the Catchment|within 10 Kms. radius of the proposed site.

(ii) Topography of the area indicating gradient, aspects & altitude.

(iii) Vulnerability to erosion.

- (c) Pollution sources existing in the 10 Km. radius and their impact on quality of air, water & land:

- (d) Distance of the nearest National Park|Sanctuary|Biosphere Reserve|Monuments|heritage site|Reserve Forest :

- (e) Rehabilitation plan for quarries|borrow areas
- (f) Green belt Plan :

- (g) Compensatory afforestation plan :

4. Climate & Air Quality :

- (a) Windrose at site

- (b) Max|Min.|Mean annual temperature

- (c) Incidence of inversion :

- (d) Frequency of cyclones|tornadoes|cloud bursts:

- (e) Ambient air quality data

- (f) Nature & concentration of emission of SPM Gass (CO, CO₂, SO₂, NO₂, CH₄ etc) from the project:

- (a) Water balance site :

- (b) Lean season water availability; Water Requirement :

- (c) source to be tapped with competing users (River, lake, Ground, Public Supply)

- (d) Water quality :

- (e) Changes observed in ground water in the last 15 years and present changing & extraction details :

- (f) (i) Quantum of waste water to be released with treatment details

- (ii) Quantum of quality of water in the receiving body before and after disposal of Solid Wastes :

- (g) (i) Details of reservoir water quality with necessary Catchment Treatment Plan;

- (ii) Command Area Development Plan:

6. Solid Wastes :

- (a) Nature & quantity of solid wastes generated to be disposed :

(b) Solid waste disposal method to prevent further pollution of air, water and land:

7. Noise & Vibrations :

(a) Sources of noise & vibrations :

(b) Ambient noise level :

(c) Noise & Vibration control measures proposed:

(d) Subsidence problem if any with control measures :

8. Power requirement indicating source of supply; complete environmental details to be furnished separately, if captive power unit proposed:

9. Peak labour force to be deployed giving details of :

— Health status through preliminary screening of workforce—labour & staff both;

— Endemic health problems in the area due to waste/soil borne diseases;

— Health care system proposed;

10. (a) Number of villages & population to be displaced :

(b) Rehabilitation Master Plan:

11. Risk assessment report along with Disaster Management Plan:

12. (a) Detailed Project Report :

(b) Environmental Impact Assessment Report :

(c) Environmental Management Plan.

Prepared as per
Guidelines of
MLF.

13. Details of Environmental Management Cell.

14. Details of air & water quality monitoring stations to be set-up.

